ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Media Bite **21 Sept, 2020**

Shri A.K. Antony, Shri Ahmed Patel, Shri K.C. Venugopal and Shri Randeep Singh Surjewala addressed media at AICC Hdqrs, today,

Shri Randeep Singh Surjewala said- Welcome Friends! A meeting of the AICC General Secretaries and In-charges was held today. Shri A.K. Antony Ji, Shri Ahmed Patel Ji, Shri K.C. Venugopal Ji, myself, we will now brief you about the future plans of the Indian National Congress as decided under the leadership of Smt. Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi. I would now request Antony Ji to say a few words to you.

Shri A.K. Antony said- Congress Party is launching an agitation against this Government for passing these anti-farmers, anti-people laws, throwing all the conventions and rules of the Rajya Sabha, Lok Sabha and also has passed it. So, from September 24th onwards, Congress Party is launching an all India agitation asking the Government to repeal these anti-farmer, anti-people, anti-poor black laws.

श्री अहमद पटेल ने कहा कि यह सरकार अहिस्ता-अहिस्ता डिक्टेटोरियलशिप और ....शाही(inaudible) की तरफ जा रही है, जिसका अनुभव हमने पार्लियामेंट के दौरान किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। जिस तरह से प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ एकतरफा रवैया रखकर, जैसे प्रतिपक्ष है ही नहीं, उसी तरह का रवैया उनका रहा। पर ये इशू बहुत ही महत्वपूर्ण था, यह एग्रीकल्चर बिल जो पास किया है, जो एक्ट बनने जा रहा है, खासतौर पर ना किसान के हित में है, ना राज्य सरकारों के हित में है और ना ही जो श्रमिक हैं, जो गरीब वर्ग है, उसके हक में है, उसके हित में है, क्योंकि फूड प्रिक्योरमेंट, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी, सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं। पार्लियामेंट में हमने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन इस इशू को हम जनता तक, किसान तक और गरीब लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक्ट से काफी नुकसान किसानों को, गरीब वर्ग को होने वाला है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष और फॉर्मर कांग्रेस अध्यक्ष, उनके निर्देश पर आज मीटिंग बुलाई गई थी और जिसमें एक प्रोग्राम बनाया गया है। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, प्रदेश, जिला और ग्रामीण स्तर तक हम जाना चाहते हैं। किसानों जागृत तो हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से इस इशू को, पंजाब, हरियाणा में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, तो हम गांव-गांव जाकर किसानों के जो हस्ताक्षर हैं, उनके सिग्नेचर (हस्ताक्षर) लेने की कोशिश करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग, किसान भाई-बहन और श्रमिक वर्ग परेशान है, तो इस इशू में, ये तो उनका इशू है, बिल्कुल सहयोग मिलेगा और जो प्रोग्राम डिटेल है, उसके बारे में पहले के.सी. वेणु गोपाल जी ब्रिफ करेंगे, फिर सुरजेवाला जी आपको विवरण देंगे, डिटेल देंगे।

Shri K.C. Venugopal said- General Secretaries and In-charges meeting has been held in the AICC office. Since the spread of Covid Pandemic in our country, this is the first

physical meeting, we have organised in the AICC office. As A.K. Antony Ji, Ahmed Patel Ji told about it, this meeting has been done under the direction of Hon'ble Congress President and former Congress President Rahul Gandhi Ji. We discussed the latest political situation in the country, especially the farmers' agitation.

The way, in which the Government of India is bulldozing anti-farmers law in Parliament, is totally unacceptable to the country and the people of India. What we had witnessed in Rajya Sabha yesterday and today, we didn't expect this type of attitude from a democratic Government. This type of bill, which is going to have serious apprehensions among the farmers of the country, there should be a parallel discussion, there should be a debate. What actually happened, everybody knows that the Government want to push the bill very speedily. We, people from Congress side and other opposition parties have given amendments and have given resolution, at least we demanded it referred to the Select Committee, for a wider consultation, nothing was accepted by the Government of India. With public interest in vision, it is the fundamental right of a member of Parliament to have a division on an important bill that also have been rejected and what they are telling, they are talking about the rules, they are talking about the procedure of the Parliament, they are talking about the healthy parliamentary democracy. Unfortunately, our Prime Minister himself is misleading the country by saying that we have done, the opposition have done some mistake.

We raised the voice of the farmers in the house that is our duty, we think, that is our preliminary duty to raise the voice of the farmers that is what we have done yesterday and today. They have suspended our 8 MPs, but, this suspension will not help Modi Ji for suppressing the farmers' agony and pain. For raising the farmers' agony and pain in the house and outside the house, therefore, today we have decided to have a series of programmes. We are starting a national agitation; we are totally with farmers' organizations, those who are fighting on the streets. We are totally with those political parties, who are fighting for the cause of the farmers, therefore the Indian National Congress is planning for a National agitation in support of all the farming organizations of the country.

First of all, a series of physical Press Conference may be held in each state on 24th September, 2020. Number two, PCC Presidents, CLP leaders along with all MPs, MLAs, Ex-Ministers, Ex- MPs, Congress candidates must walk from PCC office or a designated point like Mahatma Gandhi statue up to Raj Bhawan at every state headquarters and submit the memorandum to Governor addressed to the President of India on Agriculture Bills. English and Hindi copy will be given to the PCCs and they will put up a memorandum to the President of India through the Governor of every state.

On 2nd October, 2020, birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri Ji, we would observe as a 'Kisan Mazdoor Bachao Diwas', 'Save Farmers and Farm-Labourers Day'. We will hold Dharnas, Marches at every assembly headquarters and district headquarters across India on the Agriculture bills, wherein we will demand for the immediate withdrawal. We will try to court arrest at every assembly and district headquarters.

On October 10th, all state units will organise state level 'Kisan Sammelan' at every state headquarters and any other important place in the state.

And finally, one more programme, we are starting a massive signature campaign. We will collect 2 crore signatures from the farmers throughout the India and we will submit the memorandum on Pt. Jawahar Lal Nehru's birthday, November 14th. The memorandum will be submitted to the President of India. This is for the programme we have talked today and after some days, we will meet again and we will formulate the further programmes.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जैसा आदरणीय ए.के. एंटनी जी ने, माननीय अहमद पटेल जी और केसी वेणु गोपाल जी ने कहा संसद के अंदर संसदीय लोकतंत्र का गला घौंटा जा रहा है और सड़कों पर किसान को लाठियों से पीट कर प्रजातंत्र का गला घौंटा जा रहा है। खेत और खलिहानों में, सड़कों और बाजारों में, मजदूरों और किसान की आजीविका छीनी जा रही है और संसद के अंदर उनके नुमाईंदों की आवाज दबाई जा रही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बंदी सरकार बन गई है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाकर व्यापार बंदी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाकर देशबंदी की और अब खेत और खलिहान बंदी करने की तैयारी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी कर ली है और उस जन आंदोलन के कई चरण आदरणीय वेणु गोपाल जी ने बताए।

आज 21 तारीख है, अगले 72 घंटे में कांग्रेस के नेता, महासचिव, इंचार्ज और दूसरे प्रमुख नेतागण प्रेस वार्ताओं के माध्यम से हर स्टेट हैडक्वार्टर तक जाकर मोदी सरकार की ढोल की पोल खोलेंगे। 28 तारीख तक अगले 4 दिनों में महामहिम राज्यपाल महोदयों को हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जहाँ मुख्यमंत्रीगण हैं, वहाँ मुख्यमंत्रीगण, जहाँ विपक्ष के नेता हैं, वहाँ विपक्ष के नेता प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। कांग्रेस कार्यालयों या महात्मा गांधी जी की मूर्ति से राजभवनों तक और ये मांग रखेंगे ज्ञापन देकर कि ये तीन कृषि विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। 2 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान की हर विधानसभा में, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में, कांग्रेस पार्टी के जिला, कांग्रेस प्रधान, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे उम्मीदवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा धरना प्रदर्शन करेंगे और इन काले कानूनों के खिलाफ ज्ञापन देंगे।

10 अक्टूबर को हर राज्य के अंदर बड़े किसान सम्मेलन बुलाएं जाएंगे ताकि किसान की पुकार जा सके और 31 अक्टूबर जो इस देश के लिए शहादत का एक महत्वपूर्ण दिन है, 31 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंति से 31 अक्टूबर के बीच में कांग्रेस के साथी हर गांव जाएंगे और इन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ दो करोड़ दस्तखत किसानों और गरीबों के इक्कट्ठे करके लाएंगे जो 14 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे।

इस बैठक का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 73 सालों में व्यवस्था पैदा की थी, उस व्यवस्था के तीन अंग हैं – पहला है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है कृषि उपज खरीद प्रणाली और तीसरा है राशन की दुकान पर गरीब को राशन देना। मोदी जी ने इन तीन काले कानूनों से केवल किसान और खेत मजदूर पर नहीं, इस देश के एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों पर हमला बोला है, उनकी रोजी-रोटी पर हमला बोला है, देश के गरीब पर हमला बोला है, उनके पेट पर हमला बोला है, उनकी थाली पर हमला बोला है और कांग्रेस एक-एक कतरा खून का बहाकर, जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष करेगी।

एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अभी-अभी इस देश की त्रासदी देखी, जिस देश के प्रधानमंत्री को रबी और खरीफ फसलों का अंतर नहीं पता, वो किसान और मजदूर का भला क्या करेगा? प्रधानमंत्री का सबसे ताजा ट्वीट पढ़िए, उन्हें यही नहीं पता कि धान की फसल जो है, वो रबी फसल है या खरीफ फसल है। उन्हें यही नहीं पता कि अरहर की फसल जो है, दाल की, वो रबी है या खरीफ की फसल है, अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को धान और गेहूं का अंतर नहीं पता, रबी और खरीफ का अंतर नहीं पता, वो किसान का भला क्या खाक करेगा? इसलिए कहा है कि नीम हकीम खतरे जान, अब पूरे देश के मजदूर और किसान की जान खतरे में है। साथियों, तैयार हो जाईए क्योंकि जो दुकान से आप परिवार के लिए राशन खरीदते हैं, आप और आपके दर्शक, उनकी भी रोटी और कीमत मोदी जी छीनना चाहते हैं।

On a question about the farmers' issue Shri Surjewala said- The question my friend is, how will the farmers get MSP, once the APMC or the farmers markets are abolished? Who will give the MSP to the farmer and how will he get that MSP? Once, there is no APMC, farmer can't take his produce to the Mandi then will FCI go to 15.5 crore farmer fields to give MSP, that is impossibility, FCI doesn't go to 40 thousand APMCs also. The net result will be 4 or 5 big corporate houses will buy farmers' crop at whatever rate they may deem fit, Modi Ji can say whatever he wants to while feeding peacocks, but, MSP is given on the ground with the cumulative power of the farmer in the agriculture markets, he is abolishing that, why has he not written Mr. Modi, will you tell the nation? Why has he not written the word MSP in the 3 laws? Why is he not ready to now write a guarantee that no crop in India will be sold below MSP? A valid point is being made by our senior leader Mr Patel, if APMC will remain, if MSP will remain, why has he brought this law? The same companies can then go to the APMC and buy crop at APMCs. The whole idea of abolishing mandis, the whole idea of abolishing small-small shopkeepers and labourers, the whole idea of attacking farm labourers is to attack the PDS system, the ration system through which… when the crop is procured, it is given to the poor, the rice and the wheat goes to the poor, the dals, the pulses go to the poor, so, I think, the Prime Minister is not only misleading the country, but, speaking blatant lies.

On another question about the Shiromani Akali Dal, Shri Surjewala said- Shiromani Akali Dal is acting with double speak and dishonesty. Political dishonesty has been synonymous with Shiromani Akali Dal. Is it not true that Harsimrat Kaur Badal Ji was a minister when these black laws were passed in the cabinet and she assented to that? Is it not true that between June to September, Sardar Prakash Singh Badal, Sardar Sukhbir Singh Badal and Smt Harsimrat Kaur Badal continued to support the laws, only now when the farmers' in Punjab said, you can't enter Punjab, they got scared and collusively resigned, but, why have they not withdrawn the support from Modi Government? Why are they part of NDA? Why do they continue to support an anti-farmer Government, so they can't indulge in double speak and dishonesty of this nature?

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC